

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 363  
उत्तर देने की तारीख 27 नवंबर, 2024

निजी दूरसंचार सेवाप्रदाताओं द्वारा टैरिफ प्लान में वृद्धि

363. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में कार्यरत निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल आदि ने वर्ष 2024 के दौरान अपने टैरिफ में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार की निगरानी और विनियमन होने के बावजूद एकतरफा टैरिफ बढ़ाने का आधार क्या है;
- (ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले 35 हजार करोड़ रुपये के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों को टैरिफ में की गई वृद्धि वापस लेने का निदेश देने का इरादा है; और
- (ङ) यदि हां, तो इन कंपनियों को ऐसा निदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर  
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

- (क) जी हां, हाल ही में निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने टैरिफ में वृद्धि की है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड) द्वारा टैरिफ में 11% से 25% तक वृद्धि की गई है।
- (ख) से (ङ) वर्ष 2004 में दूरसंचार सेवा बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा को देखते हुए विश्व के कई देशों की तर्ज पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल दूरसंचार सेवाओं हेतु फोरबेअरन्स की नीति अपनाई थी। इसका तात्पर्य यह है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता

(टीएसपी) बाजार के मांग और आपूर्ति के नियंत्रक प्रभावों के आधार पर प्रतिस्पर्धी बाजार में दूरसंचार सेवाओं हेतु टैरिफ तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) की आवश्यकताओं के अनुरूप दूरसंचार सेवा प्रदाता बाजार में उनके लॉन्च होने के 7 दिनों के भीतर ट्राई के पास अपने टैरिफ दाखिल करने के लिए बाध्य हैं। फिर इन टैरिफों की विनियामक सिद्धांतों के अनुपालन के लिए जांच की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पारदर्शिता, गैर-प्रलोभन और गैर-भेदभाव के सिद्धांत शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि बाजार में अभी भी पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है तथा कम से कम 4 सेवा प्रदाता प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रतिस्पर्धी प्लान पेश कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय दूरसंचार दरें विश्व में तथा भारत के पड़ोसी देशों में भी सबसे कम दरों में से एक हैं।